श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन्, पर्यटन का विकास मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय सरकार, जो राज्य सरकारों के विशिष्ट प्रस्ताव होते हैं, जो उनकी योजनायें होती हैं, उसमें उनकी सहायता करती है। जो हमारी आर्थिक सीमायें हैं उनमें रहते हुए हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि उनकी हम वित्तीय सहायता करें। इसके अलावा जो जगह आइडेंटिफाई की जाती है, पहचानी जाती है, उन जगहों के प्रचार और प्रसार में हम उनकी सहायता करते हैं। जहां वे सड़कों पर यात्रियों को सुविधा देने का काम करती हैं, उसमें भी हम उनकी सहायता करते हैं। लेकिन मूलत: यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। वे अपने अपने राज्यों में यह पहचान करें कि कौन कौन जगह पर्यटन स्थल हो सकते हैं। हम इस सिलसिले में राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं।

लेकिन जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव है कि हम सारी चीजें अपने हाथ में लें लें, इस पर हमने अभी कोई विचार नहीं किया है और मेरा ख्याल है कि इसको राज्य सरकारें भी पसंद नहीं करेंगी कि पर्यटन का सारा काम हम अपने हाथ में ले लें। इसलिये मैं इस सिलसिले में कोई भी कमिटमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि मैंने एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा कि बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर के जो टूरिस्ट डवलपमेंट प्रोग्राम हैं वह योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो रही हैं बिहार में (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN; Question Hour is war.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

UNDP aid tor mining projects in Orissa

*222. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state;

(a) whether the UNDP aid is likely to *he* obtained for some mining projects[1] in Orissa; and

(b) if so, what are the details of those projects?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI):(a) A Project on "Development of Gemstone Resources of Orissa State" has-been approved for assistance by UNDP.

(b) The project includes;

(i) delineation and assessment of gemstone prospects of Orissa State;

(ii) adoption of appropriate mining and processing techniques;

(iii) establishment of a modern gem testing laboratory; and

(iv) upgradation of knowledge, skill and experience of the technical personnel through training in State of art techniques.

Import of Phosphoric Acid by MMTC

*225. SHRI ASHOK NATH VERM A: Will the Minister of COMMERCE be pleas«d to state;

(a) whether it is a fact that MMTC has been designated as the Canalising Agency for the import of phosphoric acid;

(b) if so, what norms have been laid down by MMTC for its distribution; and

(c) whether MMTC has imported the phosphoric acid in crystal form or in liquid form, and what is the grade/percentage thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN):

(a) to (c) MMTC has been designated as the canalising agency for import of Phosphorid Acid with effect from 8-2-1990.

Phosphoric Acid is allocated by MMTC to various users in consultation with the Department of Fertilizer on the basis of licensed capacity, past allocations and the quantity authorised for import.

MMTC has imported phosphoric acid in liquid form. The P209 concentrate in the Phosphoric solution, imported ranges by weight between 52 to 64 per cent.

आइसक्रीम उद्योग में बड़ी फर्मों का प्रवेश

***227. डा० जितेन्द्र कुमार जैन:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आइसक्रीम उत्पादक उद्योग लघु उद्योग के लिए आरक्षित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब कुछ बड़ी फर्में भी इस उद्योग में प्रवेश कर गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा उन्हें आइसक्रीम का उत्पादन करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क) से (ग) आइसक्रीम बनाने का काम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है। जो बड़े एकक लघु क्षेत्र हेतु इसके आरक्षण से पूर्व आइसक्रीम बना रहे थे, वे कुछ शर्तों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आइसक्रीम बनाना जारी रख सकते है। ऐसे किसी भी बड़े एकक को आइसक्रीम बनाने का लाइसेंस नहीं दिया गया है जो आइसक्रीम के आरक्षण से पूर्व इसे नहीं बना रहा था।

Ban on recruitment in banks

*228. DR. NARREDDY THULASI REDDY; Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether there is a ban on recruitment in the banks;

(b) if so, what are the reasons there, for; and

(c) by when the ban is proposed "to" be lifted?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) No, Sir.

(to) and (c) Do not arise.

Upper age limit for Banking Service Recreiutment

*229. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FINANCE be' pleased to state; ' ;

(a) what is the upper age limit for Banking Service Recriutment and whether Government propose to bring it at par with UPSC age level;.

(b) whether Government also propose to follow the ' guidelines of the Receive Bank Board for Banking Service Recruitment; and

(c) whether Government also propose to constitute National Banking Selection Board? ' • .

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) ... The upper age limit for Probationary Officers in the public sector banks is 26 years. It is proposed to consider this in consultation with Reserve Bank of India (RBI).

(b) Recruitment to the officers cadre of the Reserve Bank of India is done by the Reserve Bank Seriveces Board. The upper age limit for recruitment to this cadre in the Reserve Bank of India is 26 years with certain relaxations for SC/ST etc. which are also available for recruitment of Probationary Officers in the public sector banks_ In matters of recruitment, the guidelines applicable to the Reserve Bank Services Board are not relevant to the Banking Service Recruitment Board/ commercial banks which have their